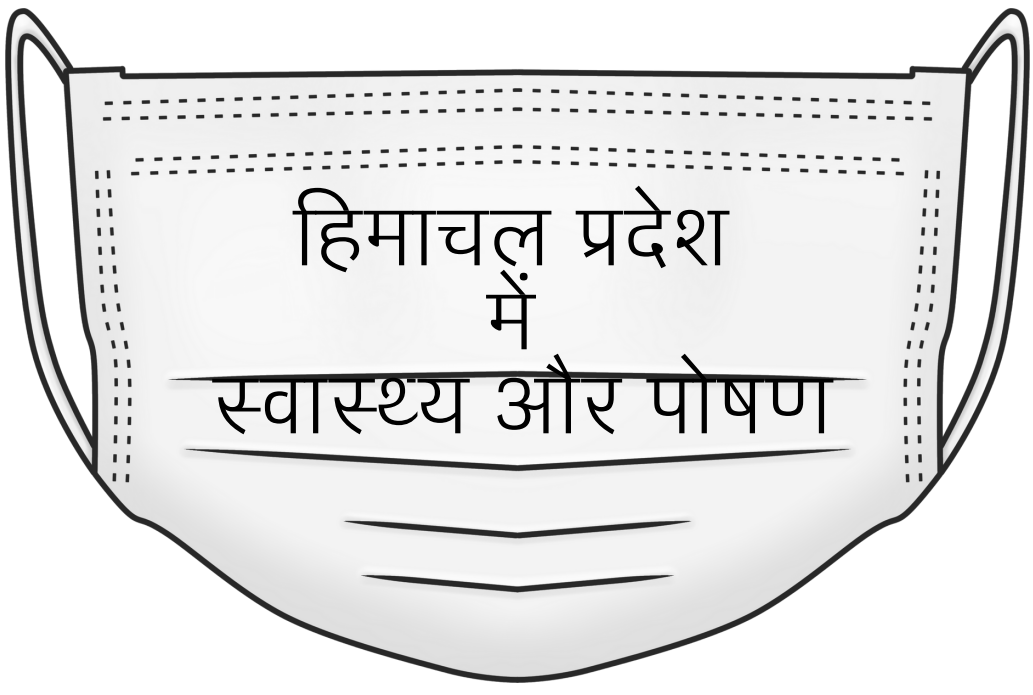

ACCOUNTABILITY INITIATIVE | हम और हमारी सरकार | CENTRE FOR POLICY RESEARCH

# हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण

## समेकित बाल विकास सेवाएँ

हिमाचल प्रदेश को पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए मांग की अपेक्षा के अनुसार 2019-20 के लिए सिर्फ 52% बजट (भारत सरकार और राज्य का हिस्सा) अनुमोदित किया। 2020-21 में पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल और दिसम्बर के बीच यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि के साथ तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए बजट में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हिमाचल प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले पात्र लोगों की संख्या में जून 2019 से जून 2020 की अवधि के बीच 2 प्रतिशत की कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में मार्च और अप्रैल 2020 के बीच नवजात शिशुओं के वजन तोलने की संख्या में 5 प्रतिशत कमी आई।

30 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत और सुपरवाइजर के लिए स्वीकृत पदों में से 17 प्रतिशत पद रिक्त थे।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पाया गया कि 5 साल से कम उम्र के 17 प्रतिशत बच्चों का वजन अपने ऊंचाई के हिसाब से सामान्य से कम है। वहीं इसी आयु वर्ग के 31 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के अनुरूप छोटे पाए गए।

## आयुष्मान भारत

धन के दोनों स्रोतों (केंद्र एवं राज्य) के उपयोग के संबंध में राज्यों के खर्च में काफी अंतर है। अक्तूबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की 62 प्रतिशत राशि को खर्च कर लिया था जबकि मार्च 2020 तक राज्य ने अपनी हिस्सेदारी का केवल 9 प्रतिशत ही खर्चा किया

राज्य कार्यक्रम इकाइयों (एसपीयू) में रिक्तियों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दायर सूचना का अधिकार के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत पद रिक्त थे जबकि राज्य स्तर पर एक भी पद रिक्त नहीं था।

पोषण अभियान ने राज्यों को धन मुहैया कराया, जिसे इनोवेशन ग्रांट या नवाचार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के रूप में भी जाना जाता है। 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से हिमाचल प्रदेश ने अपने नवाचार फंड का केवल 2 प्रतिशत ही उपयोग किया जबकि बिहार एवं राजस्थान ने क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पैसा खर्च किया।

2015-16 और 2019-20 के बीच, छह महीने से पांच साल तक के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में हिमाचल प्रदेश 1.7 प्रतिशत के साथ शामिल था। वहीं एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 की तुलना में 15-49 वर्ष की महिलाओं में अनीमिया में 05 प्रतिशत की कमी देखी गयी।

सभी आंकड़े अकाउंटबिलिटी इनिशिएटिव की बजट ब्रीफ सीरीज़ 2021-22 में से लिए गए हैं। आप https://accountabilityindia.in/budget-briefs/ पर विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।